श्रीमती राम दुलारी सिन्हा : अध्यक्ष महोदय, एक नेशनल कमीशन आन लेबर 1966 में एप्वाइंट हुआ था, उसमें बहुत से बिन्दुओं पर सुझाव दिए थे । उसमें यह भी कहा है कि the national minimum wage is neither feasible nor desirable. एक चक्रवर्ती कमेटी है, जो कि 1973 में एप्वाइंट हुई थी, उस में भी कई बिन्दुओं पर सुझाव दिए गए हैं । उसमें एक बिन्दु यह है कि National Wage structure must be evolved. भूतुलिगम कमेटी में 150 रु० प्रतिमाह मजदूरों को देने की बात है, जैसा मैंने पहले ही कहा है । सरकार इस सम्बन्ध में सतर्क है । भारत के एम्प्लायर्स और मजदूर यूनियन के प्रतिनिधियों से सरकार अपेक्षा करती है और स्टेट गवर्नमेंट्स तथा लेबर डिपार्टमेंट के सहयोग से सरकार इस समस्या को हल करने के लिए सतर्क है ।

SHRI XAVIER ARAKAL: I congratulate the hon. Minister for taking this bold step. I would like to know, who are the people who are going to examine the wage policy. Are they going to consider the previous reports, recommendations of various trade unions as well as the Committees? And when will this report be placed on the Table of the House.

SHRIMATI RAM DULARI SINHA: All the previous reports and recommendations will be kept under consideration. Further suggestions are also invited from the state governments and those will be also taken into consideration.

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

उत्तर प्रदेश के पर्वतीय जिलों को पिछड़े क्षेत्र घोषित करना

*988. **श्री हरीश चन्द्र सिंह रावत** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार को इस आशय का एक प्रस्ताव भेजा है कि उसके आठ पर्वतीय जिलों को पिछड़े क्षेत्र घोषित किया जाये ;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने उसे मंजूर कर लिया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

योजना और श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : जी, हां । सरकार को उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से सम्पूर्ण पहाड़ी क्षेत्रों सहित अतिरिक्त क्षेत्रों के लिए केन्द्रीय निवेश सहायता स्कीम को लागू करने के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए थे ।

(ख) और (ग). पहाड़ी क्षेत्रों सहित सभी पिछड़े क्षेत्रों के विकास और रियायती वित्त, निवेश सहायता, आदि की केन्द्रीय स्कीमों के सम्पूर्ण प्रश्न की योजना आयोग के एक भूतपूर्व सदस्य की अध्यक्षता में पिछड़े क्षेत्रों के विकास से सम्बन्धित राष्ट्रीय समिति ने जांच की थी । इस समिति ने औद्योगिक प्रकीर्णन से संबन्धित एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिसकी राज्य सरकारों, सम्बन्धित केन्द्रीय मंत्रालयों और वित्तीय संस्थाओं के परामर्श से जांच की जा रही है ।

Enhancement of Special Central Assistance for tribal sub-plan areas

*993. SHRI BHEEKHABHAI: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state: